

सम्पादकीय

अपनों के दायरे से आगे

खास बात यह कि इसमें सिर्फ उन व्यवहारों को शामिल किया गया, जिनके लिए हमें कुछ खर्च नहीं करता पड़ता या जिनमें समय लगाने की जरूरत नहीं होती। 31 देशों के लोगों पर की गई इस स्टडी के मुताबिक, भारत इस मामले में नीचे से तीसरे नंबर पर है। अंतरराष्ट्रीय रिसर्च जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ नैशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज में पिछले सप्ताह प्रकाशित एक स्टडी रिपोर्ट ने बहुतों का ध्यान खींचा। इस स्टडी में पहली बार अलग-अलग देशों के संदर्भ में यह देखने की कोशिश हुई कि सामाजिक रूप से सघेत व्यवहार करने के मामले में किस देश के लोग कहां खड़े हैं? सामाजिक रूप से सघेत व्यवहार से मतलब है उन लोगों के हितों का, उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना, जो सीधे तौर पर हमसे जुड़े नहीं हैं, जिन्हें हम जानते नहीं हैं। खास बात यह कि इसमें सिर्फ उन व्यवहारों को शामिल किया गया, जिनके लिए हमें कुछ खर्च नहीं करता पड़ता या जिनमें समय लगाने की जरूरत नहीं होती। 31 देशों के लोगों पर की गई इस स्टडी के मुताबिक, भारत इस मामले में नीचे से तीसरे नंबर पर है। तुर्की और इंडोनेशिया ही उससे नीचे हैं। इस मामले में टॉप पर है जापान, जहां लोगों के अच्छे व्यवहार का प्रतिशत 72 है। ऑस्ट्रेलियाई 69 फीसदी और मेक्सिकन 68 फीसदी के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर हैं। भारत 50 फीसदी पर है। उल्लेखनीय है कि दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखने का मतलब सिर्फ सौंरी -थैंक्यू कहना नहीं है। वरना दुनिया के सबसे विनम्र लोगों वाला देश कनाडा इस स्टडी में 57 फीसदी पॉइंट के साथ कम स्कोर वाले देशों में शामिल नहीं होता।

बहरहाल, यह नंबरिंग खास मायने नहीं रखती। महत्वपूर्ण यह तथ्य है कि आम तौर पर हमारा व्यवहार हमारी व्यापक सामाजिक चेतना पर निर्भर करता है, जो काफी हद तक हमारे सांस्कृतिक परिवेश से तय होती है। विभिन्न देश, समाज इस मार्गे में अलग-अलग स्थिति में क्यों हैं, यह एक जटिल सवाल है। इस स्टडी रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि विभिन्न देशों की अलग-अलग स्थिति की व्याख्या करने के लिए और अध्ययन करने की जरूरत है, लैकिन दो बातें साफ हैं। एक तो यह कि जिन देशों और समाजों में लोग उच्चत सामाजिक चेतना से लैस हैं यानी जहां वे अनजान लोगों के हितों, उनकी भावनाओं को लेकर भी सचेत होते हैं, वहां पारस्परिक विश्वास ज्यादा होता है जिसका सकारात्मक प्रभाव राजनीतिक, आर्थिक नीतियों और विकास पर होता है। उदाहरण के लिए, वहां कड़े कानूनों की जरूरत नहीं पड़ती और माहौल में खुलापन होता है। दूसरी बात यह है कि ये सामाजिक मानदंड एक जैसे नहीं रहते। समय के साथ इनमें बदलाव आता है। मतलब यह कि चाहे जितनी भी जटिल प्रक्रिया हो, उसका सावधानी से विश्लेषण करते हुए बदलाव की इस प्रक्रिया को सकारात्मक मोड़ दिया जा सकता है। अगर अपने देश के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में इसकी पड़ताल की जाए तो वसुधैर कुटुंबकम यानी पूरी पृथक्की को परिवार मानने के आदर्श के साथ अपने ही समाज के कुछ खास हिस्सों को खुद से अलग मानने के यथार्थ का विरोधाभास अच्छी केस स्टडी हो सकता है।

जनरल मोटर्स, हार्ले डेविडसन और अब फोर्ड मोटर...क्यों भारत छोड़ रही हैं विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियाँ

नीरज कुमार दुबे

फोर्ड मोटर कंपनी ने जब कहा कि वह देश के अपने दो संयंत्रों में वाहन उत्पादन बंद कर देगी और केवल आयातित वाहनों को ही बेचेगी तो एक चिंता की लहर तो दौड़ी ही साथ ही भारत में निवेश को उत्सुक ऑटोमोबाइल कंपनियों को भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार पर मजबूर होना पड़ा। विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियां भारत में आती तो बड़े जोरशोर से हैं लेकिन सही रणनीति नहीं होने के चलते उन्हें अपना कारोबार समेटना पड़ जाता है। जनरल मोटर्स और हार्ले डेविडसन के बाद इस सूची में नाम जुड़ गया है फोर्ड मोटर का। देखा जाये तो कोरोना से उपजे हालात और ऑटोमोबाइल सेक्टर में चल रही मंदी से अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड की कमर टूट गयी है और उसने भारत में अपने संयंत्रों पर ताला लगाने का फैसला किया है। बताया गया है कि दो अरब डॉलर का नुकसान झेलने से कंपनी की हालत पतली हो गयी है। हालांकि कंपनी के इस ऐलान से उन लोगों की चिंता बढ़ गयी है जिनके पास फोर्ड मोटर की गाड़ी है। लेकिन कंपनी ने ऐलान किया है कि जिन लोगों के पास फोर्ड की गाड़ी ही उन्हें सर्विस पहले की तरह मिलती रहेगी। लगभग तीन दशकों से भारतीय बाजार में मौजूद अमेरिका की प्रमुख वाहन कंपनी फोर्ड मोटर कंपनी ने जब कहा कि वह देश के अपने दो संयंत्रों में वाहन उत्पादन बंद कर देगी और केवल आयातित वाहनों को ही बेचेगी तो एक चिंता की लहर तो दौड़ी ही साथ ही भारत में निवेश को उत्सुक ऑटोमोबाइल कंपनियों को भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार पर मजबूर होना पड़ा। फोर्ड कंपनी ने अपने चेन्नई (तमिलनाडु) और साणंद (गुजरात) संयंत्रों में लगभग 2.5 अरब डॉलर का निवेश किया है, मगर भारत में कड़ी प्रतिस्पर्धा

मुफ्त

भरत स्वनश्चनवाला

सरकार के राजस्व का उपयोग पार्टी के हितों को साधने के लिए किया जाता है। जैसे यदि कांग्रेस सरकार ने 2009 में लोन माफ़ी का बायदा किया अथवा वर्तमान में केन्द्र सरकार एलपीजी गैस के सिलेंडर बांट रही है तो इसका लाभ पार्टी विशेष को मिलता है, जबकि इन मुफ्त सुविधाओं को वितरित करने का भार सरकार के राजस्व पर पड़ता है। अतः उच्चतम न्यायालय ने हाल में ही नोटिस जारी किया है कि चुनाव पूर्व इस प्रकार के बायदों पर रोक क्यों न लगाई जाए? बीते समय में इंग्लैण्ड के चुनाव में वहां की लेबर पार्टी ने जनता को मुफ्त ब्राइडैंड, मुफ्त बस यात्रा और मुफ्त कार पार्किंग जैसी सुविधाओं का प्रलोभन दिया था। हम भी क्यों पीछे रहते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ वर्ष पूर्व छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए गये, तमिलनाडु में चुनाव पूर्व किंवदन ग्राइंडर और साइकिल वितरित करने का आश्वासन दिया गया, दिल्ली में एक सीमा के अंतर्गत मुफ्त बिजली और पानी दिया जा रहा है और केन्द्र सरकार द्वारा मुफ्त गैस सिलेंडर, एलईडी बल्ब और खाद्यान्न वितरित किये जा रहे हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार के सीधे वितरण से जन कल्याण हासिल होता है। जिस छात्र को लैपटॉप मिल जाता है वह उससे अपने कौशल को सुधार सकता है और जीवन में आगे बढ़ सकता है। लेकिन कहावत है कि

तालिबान से न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी, भारत करे तो क्या करे?

अनुराग मिश्र

अपने देश में एक कहावत है बदमाशों से दूर ही रहते हैं। उनकी न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी। 'बदमाशों' की जगह अपने-अपने इलाके में नई कहावतें गढ़ ली गई हैं, गो दूसरी बात है। फिलहाल बात बदमाशों की ही नहीं करते हैं। ऐसे ही कुछ बदमाश भारत के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में सत्तासीन हो चुके हैं। भारत (पाकिस्तान के कज्जे वाले जम्मू-कश्मीर बॉर्डर से) करीब 106 किमी की सीमा अफगानिस्तान से साझा करता है। तकनीकी लिहाज से देखें, तो उस देश में बदलते घटनाक्रम से भारत के अलर्ट रहने की यह एक बड़ी वजह है। इतना ही नहीं, भारत की लुक ईस्ट नीति हो या लुक वेस्ट, हमने हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते चाहे हैं, गो बात अलग है कि पाकिस्तान और चीन जैसे दो देशों ने कई बार पीठ में छुरा घोपने का काम किया है। पर, सर्व भवन्तु सुखिन का पाठ करने वाले भारतीयों की संस्कृति हमें सब के कल्याण की ही शिक्षा देती है। ऐसे में अफगानिस्तान में जब आतंकियों ने सरकार बनाली है, भारत करे तो क्या करे? तालिबान के लड़ाके (जैसा कि कुछ लोगों कहते हैं), जिहादी (ऐसा लगता है बड़े पाक मिशन पर निकले हों) जैसे शब्दों से अपना दामन छिपाने वाले इन खूंखार आतंकियों को आतंकी न कहा जाए तो क्या कहें। जो किसी महिला के पुरुष से बात करने पर सजा दें, बच्चियों को पढ़ने न दें, पढ़ने की कोशिश पर गोली मार दें, खुलेआम कलेआम करें, महिलाओं का शोषण और दरिद्रिया की हड्डे पार करें, ऐसे अशांति पसंद खूंखार लोगों से कैसे बरताव किया जाए। यह सवाल पाकिस्तान और कुछ हद तक चीन को छोड़कर परी दुनिया के सामने है। जैसे किसी लोकतांत्रिक देश में शीर्ष पद होते ही नाम तो वैसे तालिबान सरकार में भी रखे गए हैं, बस बैठने वालों के हाथ खून से सनेह हैं। पश्तो जबान में छात्रों को तालिबान कहते हैं। पर वहां जो सरकार बनी है उसमें पीएम, गृह मंत्री भी वैधिक आतंकवादी हैं। पाकिस्तान, कतर, तुर्की जैसे इस्लामिक देशों से अलग-अलग तरह की मदद पा रहे तालिबान की लीडरशिप बंदूक के दम पर राज चलाएगी या दुनिया में अपनी सरकार को मान्यता दिलाने के लिए आतंकवाद से तौबा करेगी, यह भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल रवैया तो सुधार की तरफ नहीं दिख रहा है। किंतु 2.0 की बात की जाए पर, बीते एक महीने में अलग-अलग घटनाओं से यही साबित हआ कि तालिबान तरीका भले बदल ले

अलग धनाजा से यहा साबित हुआ। कि तालिबान तराका मेल बदल में पर उसकी नीयत नहीं बदलने वाली।

अपने देश में भी खबरों और ट्रीटमेंट में तालिबान चर्चा में है। ओवैसी से अपना पुराना वीडियो दिखाकर कह रहे हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि सरकार तालिबान से बात करे, अब देखो वो सरकार बना दैठे हैं। पूर्वी राजनयिकों की राय है कि फिलहाल तालिबान और दूसरे मित्र देशों के कदमों का इंतजार करना चाहिए। हालांकि भारत कितना वेट करेगा? करीब 23 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का वहां निवेश है, क्या उसे भुला दिया जाए? भारत ने वहां की संसद बनवाई, उसे दूटने दिया जाए। अगर हमने तालिबान से दूरी बनाई और उनसे मुहू मोड़ लिया तो इस बात की पूरी आशंका है कि पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ उकसाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तालिबान ने इस्लामिक शरीयत पर सरकार चलाने का ऐलान किया है। ऐसे में धर्म के नाम पर उकसाना, बरगलाना ज्यादा आसान होगा। वैसे भी तालिबान की टॉप लीडरशिप मतलब बड़े आतंकियों की ओर से कई बार कहा जा चुका है कि मुसलमान होने के नाते कश्मीर पर बोलने का उनका हक है। मतलब साफ है तालिबान मुस्लिम हितेषी बताकर दुनियाभर के मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर सकता है। वे तो यहीं चाहेंगे कि दुनियाभर में खासतौर से आसपास के देशों में शरिया ही चले। देलर देख लीजिए, तालिबान में आतंकी सरकार बनी। वहां की संसद में जनप्रतिनिधियों की सीट पर अँटोमैटिक

हाथियार लिए आतंकियों को तस्वीर मोड़िया मे आइ, तो भारत मे कुछ हमदर्दी का दिल बाग-बाग हो गया। वे कहने लगे कि तालिबान बदल गय है, कुछ ने तो इसे भारत की आजादी के क्रांतिकारियों से जोड़ दिया कुछ नेताओं को समझ में नहीं आया तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तालिबान का फॉर्म्युला समझाने लगे। मतलब ऐसे गिने-चुने लोग माहील खराब करने लगे हैं और पूरी संभावना है कि आगे भी तालिबान के फैसलों पर ये गुणागान करके गंध फैला सकते हैं।

सवाल फिर रही, भारत करे तो क्या करे? अब तक भारत वेट एं

वाँच की मुद्रा में है। भारत सरकार पीएम, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विदेश मंत्री, सचिव अलग-अलग स्तरों पर अपने मित्र देशों से संपर्क में हैं और अफगानिस्तान के हालात पर मंत्रिया चल रही है। कट्टरपंथी और खुंखार आतंकी पीएम या दूसरे मंत्रियों से कैसे वार्ता की जाए, कैसे उन्हें बुलाया जाएगा, या अगर वे न्योता देते हैं तो वहां जाया जाए। यह सवाल भारतीय लीडरशिप में कौंध रहा होगा। 1996 में भले ही हमने उनका सरकार को मान्यता नहीं दी थी, पर अब 2021 में हालात काफी बदल चुके हैं। दुनिया से अलग कटकर रहते हुए प्रतिबंधों के कारण आतंकियों के लिए मुश्किलें तमाम होंगी। वे दूसरे दशों की यात्रा नहीं कर सकते इनके नाम से कोई देश वीजा नहीं दे सकता, न हथियार खरीद और बेच सकते हैं। न प्लेन न शिप का इस्तेमाल होगाछ। पर यह भी तो समझिया कि ये आतंकी हैं इनके शब्दकोश में वैध और कानूनी जैसे शब्द नहीं हैं श्रीनगर से 500 किमी की हवाई दूरी पर बसे काबुल में तालिबान का राज आते ही अपने घरों में बैठकर गुणा-गणित लगा रहे कश्मीर के सियासतदान फौरन उमीद और सच्ची शारिया की बातें करने लगे हैं। दरअसल, धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे ने कई तरह की दूरियां पैदा कर दीं, जिसे या तो भरने नहीं दिया गया या बनाए रखा गया क्योंकि सियासी लोगों का फायदा इसी में था। शायद यही वजह है विं इंसानियत या भारतीयता के नाम पर एकजुटता कम और धर्म के नाम पर एकजुटता ज्यादा असर करती है। कश्मीर को फिलहाल इससे बचाए रखना होगा।

वैसे भी 370 के खत्म होने के बाद कश्मीर के सियासी लोगों के पास मुद्रे खत्म हो गए हैं और उनकी पहुंच सीमित हो गई है। वे यह जरूर चाहेंगे कि कश्मीर की दुनिया में चर्चा हो, आतंकी कश्मीरी मुसलमानों की बात करें जिससे वे अपने समीकरण साथ सकें। फिलहाल, आतंकवाद पर नियंत्रण है और सेना को हालात से निपटने के लिए खुली छूट है। ऐसे में सियासी साजिश से संभलकर रहना होगा। अबतक कश्मीर का

सुलगाने को साजश पाकस्तान से हाता रहा है, अगर काबुल में भी लश्कर-जैश-हक्कानी की चली तो नई टेंशन खड़ी हो सकती है। इसकी वजह भी है। दरअसल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बड़े कठुरपथियों के स्कूल एक ही हैं। आतंकियों वाली सरकार बनी तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक बार फिर यह स्कूल चर्चा में है। इसका नाम है जार्मिया दारुल उलूम हक्कानिया। जानकार कहते हैं कि यह तालिबान की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, जहां से पढ़ने वाले छात्र पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक, राजनीतिक और सैन्य आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे हैं। तालिबान की नई सरकार में कई मंत्री यहां से पढ़कर निकले हैं। इसकी बुनियाद पाकिस्तान बनने के एक महीने बाद रखी गई थी और यह पैशावर के पास स्थित है। साफ है कि दीन-दुनिया की जो बातें यहां बताई गई हैं वही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कठुरपथियों के दिलोदिमाग में घुसी हैं। फिर उनसे प्रगतिशील विचारधारा की उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, जैसा कि अपने देश में कुछ हमर्दद अलाप रहे हैं। तालिबान ने कश्मीर के मसलमानों की चर्चा कर मंशा साफ कर दी है। भारत सरकार और एजेंसियां अलर्ट हैं। वहां 'आतंकी सरकार' बनने के दो दिन बाद ही गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उपराज्यपाल, खुफिया एजेंसियों के चीफ्स के साथ बैठक की।

हालांकि, वेट एंड वॉच की मुद्रा से एक समय भारत को बाहर निकलना ही होगा और फिर दुनिया के देश अपने-अपने हिसाब से कदम उठाएंगे। भारत ऐसी जटिल परिस्थिति में उसी कहावत 'ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर' पर आगे की योजना बना सकता है। भारत के लिए एक अच्छा और सुरक्षित विकल्प यही हो सकता है कि हम तालिबान के साथ अपने हितों के मुताबिक बातचीत शुरू करें, जिससे पाकिस्तान या चीन को उसके कान भरने या भारत के खिलाफ नापाक मंसूबों के कामयाब होने का मौका न मिले। हां, ये अलग बात है कि लोकतांत्रिक सरकारों से अलग हमें आतंकी सरकार मानकर ही उनसे संवाद बनाना होगा। यहां प्यार की झप्पी वाली बात नहीं होगी। अभी तो कई मुस्लिम देशों की खैरात पर तालिबान सरकार चला रहा है, पर कब तक? एक समय उसे भी अर्थव्यवस्था को समझना होगा और अपने फायदे के लिए दुनिया के देशों से संबंध बनाने हौंगे। हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, पाकिस्तान और चीन से पहले ही तनातनी चलती रहती है, अगर अफगानिस्तान में भारत के खिलाफ 'शून्य' बनने दिया गया तो एक नया मोर्चा तैयार हो जाएगा, जो हमारे हित में नहीं होगा।

जाति जनगणना के खिलाफ थे नेहरू, पटेल

उमेश चतुर्वेदी

यह संयोग ही है कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी में जुटा है, तभी जातीय जनगणना को लेकर राजनीति तेज हो गई है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर जाति को लेकर हमारे स्वाधीनता सेनानी क्या सोच रहे थे। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी के उस लेख का जिक्र किया जा सकता है, जो 'यंग इंडिया' के एक मई 1930 के अंक में छपा था। इसमें गांधी जी ने लिखा है, 'मेरे, हमारे, अपनों के स्वराज में जाति और धर्म के आधार पर भेद का कोई स्पान नहीं हो सकता।'

स्वराज सबके लिए, सबके कल्याण के लिए होगा।' बापू की इस भावना का संविधान सभा ने भी द्यान रखा। लेकिन आजादी के बाते जैसे-जैसे जातीय गोलबंदी की राजनीति तेज हुई, बापू के इन शब्दों

का प्रभाव कम होने लगा। हर जाति अपने-अपने खांचे में और मजबूत होने का राजनीतिक ख्वाब देखने लगी। जातीय गोलबंदी की राजनीति को जाति आधारित जनगणना में अपनी राह दिखने लगी। आश्चर्य नहीं कि पिछड़े वर्गों की स्थिति पर 1980 में रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले बीपी मंडल ने भी यह मांग सामने रखी। यह बात और है कि तब के गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने इसे नामंजूर कर दिया था। अंग्रेजों ने 1931 में जो जनगणना कराई थी, उसका एक आधार जाति भी थी। दूसरे विश्व युद्ध के चलते 1941 में जनगणना नहीं हुई। भारत को तोड़ने के लिए अंदरूनी स्तर पर अंग्रेज जिस तरह का कुचक्कर रच रहे थे, संभव है कि अगर 1941 में जनगणना हुई होती तो उसमें भी जाति को आधार बनाया जाता। आजादी के बाद जब 1951 की जनगणना की तैयारियां हो रही थीं, तब भी जाति जनगणना की मांग उठी। लेकिन तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल ने इसे खारिज कर दिया था। तब पटेल ने कहा था, ‘जाति जनगणना देश के सामाजिक ताने-बाने को बिंगाड़ सकती है।’ इसका समर्थन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू, ऑबेंडकर और मौलाना आजाद ने भी किया था। इसके पहले संविधान सभा की एक बहस में भी पटेल गांधी जी के विचारों के मुताबिक आगे बढ़ने की मंशा जताते हुए जाति आधारित आरक्षण की मांग को खारिज कर चुके थे।

भारतीय स्वाधीनता आदोलन सिफर राजनीतिक आदोलन नहीं था। उसमें सामाजिक सुधार के भी मूल्य निहित थे। स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस भावी भारत का सपना देखा था, उसमें जातिवाद की गुंजाइश नहीं थी। संविधान और कानून के समने सभी बराबर थे। हालांकि आजादी के बाद विशेषकर समाजवादी धारा की राजनीति जैसे-जैसे आगे बढ़ी, परोक्ष रूप से जातिवादी राजनीति को ही बढ़ावा देती रही। डॉक्टर लोहिया जाति तोड़ने की बात करते थे। लेकिन उनके अनुयायियों ने जाति तोड़ने के नारे को सतही तौर पर स्वीकार किया। लोहिया मानते थे कि आर्थिक बराबरी होते ही जाति व्यवस्था खत्म तो होगी ही, सामाजिक बराबरी भी स्थापित हो जाएगी। इसलिए उन्होंने जाति तोड़ो के अपने विचार में आपसी विश्वास आधारित उदारवादी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया था। लोहिया ने लिखा है, 'जाति प्रणाली परिवर्तन के खिलाफ स्थिरता की जबरदस्त शक्ति है। यह शक्ति क्षुद्रता और झूठ को स्थिरता प्रदान करती है।' लेकिन लोहिया के अनुयायी इस सोच को धस्त करते रहे। यह अप्रिय लग सकता है, लेकिन इस तोड़क भूमिका में लोहिया के दिए नारे 'संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावें सौ मे साठ' की भी परोक्ष भूमिका रही। इस नारे के जरिए समाजवादी राजनीति का पिछड़ी जातियों में आधार मजबूत तो हुआ, लेकिन जाति टूटने के बजाय और मजबूत होने लगी। जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुईं तो जातीय राजनीति ने इसमें अपने लिए मौका देखा। हर जाति राजनीतिक अधिकार पाने के लिए अपने खोल को मजबूत करने में जुट गई। यह उलटबांसी ही है कि जिस जयप्रकाश आंदोलन से निकली गैर कांग्रेसी सरकार ने मंडल आयोग गठित किया, उसी आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के गांव सिताबदियारा में 1974 में हुई एक बैठक में जातिवादी व्यवस्था तोड़ने की दिशा में गंभीर प्रयास करने का प्रस्ताव पारित हआ था।

तब जयप्रकाश ने नारा दिया था, 'जाति छोड़ो, पवित्र धागा तोड़ो, इंसान को इंसान से जोड़ो।' जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस धरण के विषयों की चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्योंकि जाति तोड़ने की बात करने वाली राजनीति के अधिकांश अनुयायी जातियों की गोलबंदी में अपना भविष्य देख रहे थे। इसका आभास चंद्रशेखर को था, इसलिए उन्होंने जयप्रकाश से आशंका जताई थी कि आने वाले दिनों में अंदोलनकारी अपनी-अपनी जातियों के नेता के तौर पर पहचाने जाएंगे। वैसे, खुद चंद्रशेखर भी स्थानीय स्तर पर बलिया में चुनाव जीतने के लिए इसी गोलबंदी की राजनीति का सहारा लेते रहे। जातीय गोलबंदी को और आक्रामक रूप कांशीराम ने दिया। उनका नारा था, 'जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी।' यह नारा लोहिया और जयप्रकाश के नारों से आक्रामक साबित हुआ। यह समझ नहीं आता कि जातीय आधार पर हिस्सेदारी बढ़ाने की आक्रामक मांग करना और जाति तोड़ना-दोनों एक साथ कैसे संभव है? जातीय जनगणना की मौजूदा मांग भी इसी उलटबांसी का विस्तार है। जाति जनगणना के लिए तर्क दिया जाता है कि जिस जाति की जितनी संख्या होगी, उसे उतनी हिस्सेदारी देने की योजना बनेगी। केंद्रीय सूची में पिछड़ी जातियों की कुल संख्या 2633 है। रोहिणी आयोग के अनुसार, इनमें से करीब 1000 जातियों के किसी भी व्यक्ति को मंडल आयोग के मुताबिक आरक्षण का लाभ अब तक नहीं मिल सका है। शायद यही बजह है कि बिहार का माली समाज जाति जनगणना की मांग के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आया है। जाति जनगणना पर क्या फैसला होगा, यह तो भविष्य की बात है, लेकिन यह तय है कि अगर जाति जनगणना हुई तो इससे कुछ लोहियावादी दलों को फायदा जरूर होगा। यह भी सच है कि इससे जो लहर उठेगी, उसे संभाल पाना आसान नहीं होगा। अतीत के अनुभव तो यही बताते हैं।

मुफ्त वितरण की बन्दरबांट

भरत झुनझुनवाला

सरकार के राजस्व का उपयोग पार्टी के हितों को साधने के लिए किया जाता है। जैसे यदि कांग्रेस सरकार ने 2009 में लोन माफ़ी का वायदा किया अथवा वर्तमान में केन्द्र सरकार एलपीजी गैस के सिलेंडर बांट रही है तो इसका लाभ पार्टी विशेष को मिलता है, जबकि इन मुफ्त सुविधाओं को वितरित करने का भार सरकार के राजस्व पर पड़ता है। अतः उच्चतम न्यायालय ने हाल में ही नोटिस जारी किया है कि चुनाव पूर्व इस प्रकार के वायदों पर रोक क्यों न लगाई जाए? बीते समय में इंग्लैण्ड के चुनाव में वहाँ की लेबर पार्टी ने जनता को मुफ्त ब्राइडैंड, मुफ्त बस यात्रा और मुफ्त कार पार्किंग जैसी सुविधाओं का प्रलोभन दिया था। हम भी क्यों पीछे रहते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ वर्ष पूर्व छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए गये, तमिलनाडु में चुनाव पूर्व किंचन ग्राइंडर और साइकिल वितरित करने का आश्वासन दिया गया, दिल्ली में एक सीमा के अंतर्गत मुफ्त बिजली और पानी दिया जा रहा है और केन्द्र सरकार द्वारा मुफ्त गैस सिलेंडर, एलईडी बल्ब और खाद्यान्न वितरित किये जा रहे हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार के सीधे वितरण से जन कल्याण हासिल होता है। जिस छात्र को लैपटॉप मिल जाता है वह उससे अपने कौशल को सुधार सकता है और जीवन में आगे बढ़ सकता है। लेकिन कहावत है कि

किसी को मछली देने के स्थान पर मछली पकड़ना सिखाना जादा उत्तम है। चूंकि मछली देने से एक बार मछली का भोजन करके वह आनन्दित हो सकता है, लेकिन यदि उसे मछली पकड़ना सिखा दिया जाए तो आजीवन अपने भोजन की व्यवस्था कर सकता है। इसलिए सरकार के लिए जरूरी है कि वह अपने सीमित राजस्व का उस स्थान पर निवेश करे जहां कि जनता का लम्बे समय तक और अधिकाधिक कल्याण हो सके। यहां एक विषय यह है कि अकसर इस प्रकार के मुफ्त वितरण के बायदे चुनाव पूर्व किये जाते हैं जैसा कि इंग्लैण्ड में लेबर पार्टी ने चुनाव पूर्व किया है। अपने देश में कांग्रेस ने 2009 में किसानों की ओपन माफी का बायदा किया और सत्ता हासिल की थी।

तमिलनाडु में जैसा कि ऊपर बताया गया है कि किचन ग्राइंडर आदि बांटने के आश्वासन चुनाव पूर्व दिए गये। इस प्रकार के बायदे किये जाने से सरकार के राजस्व का उपयोग पार्टी के हितों को साधने के लिए किया जाता है। जैसे यदि कांग्रेस सरकार ने 2009 में लोन माफी का बायदा किया अथवा वर्तमान में केन्द्र सरकार एलपीजी गैस के सिलेंडर बांट रही है तो इसका लाभ पार्टी विशेष को मिलता है, जबकि इन मुफ्त सुविधाओं को वितरित करने का भार सरकार के राजस्व पर पड़ता है। अतः उच्चतम न्यायालय ने हाल में ही नोटिस जारी किया है कि चुनाव पूर्व इस प्रकार के बायदों पर रोक क्यों न लगाई जाए? सुप्रीम कोर्ट की यह सोच सही दिशा में है और केन्द्र सरकार को इस दिशा में स्वयं पहल करके इस-

प्रकार के चुनाव पूर्व वायदों को प्रतिबंधित करने का राष्ट्रव्यापी कानून बनाना चाहिए। चुनाव से आगे, सरकार द्वारा तीन प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं पहली सुविधा सार्वजनिक जो केवल सरकार द्वारा दो जा सकती हैं दूसरी सुविधा उत्कृष्ट जो व्यक्तिगत है लेकिन उसका समाज पर प्रभाव पड़ता है, और तीसरा व्यक्तिगत जो कि व्यक्ति विशेष मात्र को लाभ पहुंचाती है। सार्वजनिक सुविधाएं वे हैं जो सरकार ही उपलब्ध कर सकती हैं जैसे- रेलगाड़ी, गाँव की सड़क अथवा कोरिड से बचने के लिए क्या कदम उठाए जाएं इसकी जानकारी। ये सुविधा केवल सरकार ही दें सकती हैं। इसलिए सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी इस प्रकार के सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने की होनी चाहिए। इससे आगे कुछ सुविधा व्यक्तिगत लेकिन 'उत्कृष्ट' कही जा सकती हैं। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा मास्क पहनना मूलतः व्यक्तिगत सेवा है। वह बाजार से 10 रुपये का मास्क खरीदकर पहन सकता है। इसमें सरकार के द्वारा वितरण करने की जरूरत नहीं है। लेकिन व्यक्ति के मास्क पहनने से दूसरों का संक्रमण से बचाया होता है। इसलिए सरकार मास्क बांटे और लोगों को उसे लगाने के लिए प्रेरित करे तो यह सुविधा व्यक्तिगत होने के बावजूद उत्कृष्ट कही जाती है क्योंकि इससे दूसरे तमाम लोगों को लाभ होता है। इसकी तुलना में कुछ सुविधाएं मुख्यतः व्यक्तिगत कही जा सकती हैं। जैसे मुफ्त बिजली, पानी मुफ्त गैस सिलेंडर, मुफ्त सायकिल अथवा लैपटॉप।

